

झारखंड में तकनीकी शिक्षा की वर्तमान स्थिति

Poonam Bala^{1*} Dr. Ram Prakash Saini²

¹ Research Scholar, Kalinga University, Raipur

² PhD Supervisor, Kalinga University, Raipur

सार – झारखंड ने पिछले तीन दशकों में इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में अविश्वसनीय प्रगति की है। यह थीसिस भारत में तकनीकी शिक्षा के वर्तमान विकास पर चर्चा करती है, और कुछ चुनिंदा भारतीय संस्थानों - एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की तुलना प्रस्तुत करती है। एक अंतरराष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय संस्थान प्रभावी रूप से स्नातक-शिक्षण संस्थानों से लेकर शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों तक विकसित नहीं हुए हैं। तुलना छात्र के आउटपुट, कुल उपाधियों के स्नातकोत्तर के अनुपात, छात्र से संकाय अनुपात, चयनात्मकता, प्लेसमेंट, संकाय वेतन, प्रकाशन और वित्त पोषण के आधार पर की गई है।

-----X-----

परिचय

तकनीकी शिक्षा में भारत है अभूतपूर्व विस्तार का एक चरण है, एक विस्फोट द्वारा चिह्नित गुजर में छात्रों, एक पर्याप्त विस्तार की मात्रा में संस्थानों की संख्या और एक लंबी छलांग में सार्वजनिक धन के स्तर पर। शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है पारंपरिक विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा तृतीयक शिक्षा में विविधता लाने के लिए। तृतीयक शिक्षा प्रणाली जिसने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, भारत के सभी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत में इसकी बुरी तरह से आवश्यकता है। देश को ऐसे संस्थानों के नेटवर्क के लिए प्रयास करना चाहिए जो युवा पुरुषों और महिलाओं को एक योग्यता और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें जिसके साथ एक व्यक्ति रोजगार पा सके। शैक्षिक शिक्षा की जरूरत पर जोर देने के लिए किया जा तब्दील और युवा पुरुषों और महिलाओं को जो नौकरी पाने के लिए एक योग्यता लेनी चाहिए जा विभिन्न तकनीकी संस्थानों से तकनीकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार को देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए नीति बनाते समय गहरी रुचि लेनी चाहिए। यह है प्रकार की शिक्षा में आज के तकनीकी वैश्विक परिदृश्य की शिक्षा प्रणाली, उत्पाद है जो का एक बड़ा योगदान कर सकता है के लिए एक राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सामान्य और एक राज्य में विशेष रूप से। हर कोई इस आधुनिक युग में महत्वाकांक्षी है और ये महत्वाकांक्षाएं तब पूरी हो सकती हैं जब कोई विशेषज्ञ हो और उसकी उस क्षेत्र विशेष में रुचि हो। कार्य

निश्चित रूप से सफल है जो पूरी तरह से ब्याज के साथ किया जाता है और यदि छात्र शिक्षा में अपनी रुचि से व्यावसायिक क्षेत्र का चयन करते हैं तो उन्हें अपने करियर के लिए उचित दिशा मिलती है।

आज का छात्र आगे के अध्ययन और देखभाल के चयन के बारे में भ्रमित करता है ग्रेड - 10 या 12. अपनी-अपनी पसंद के अनुसार सभी के लिए गुंजाइश है। यदि यह चयन किसी दबाव या तुलना के तहत होता है, तो समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी होती है और कई बार छात्र तनाव और निराशा का शिकार होते हैं। उचित कार्यवाई होनी चाहिए कि छात्र अपनी पसंद के अनुसार अपने पेशे का चयन कर सकें। जांचकर्ताओं वर्तमान जनसंपर्क चयनित ओब एलईएम एक एन डी सी ओ एन डी यू सी टी टी एच ई एस टी नकल के रूप में एक टी तल को कश्मीर एन वू रों टी यू क ई NT s " VO सी एक टी में ओ एन एक एल मैं द समकालीन समय में टे एस।

सूचना एक राष्ट्र के विकास के साथ-साथ एक व्यक्तिगत समृद्धि की कुंजी है। धीरे-धीरे समाज को सामंतवादी से लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक से सूचना समाज में बदला जा रहा है। आज का समाज, अत्यधिक जानकारी पर निर्भर होने के नाते, समाज की लगभग सभी गतिविधियाँ सूचना, ज्ञान और शिक्षण उन्मुख हैं। सूचना एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है और बौद्धिक गतिविधि के हर क्षेत्र में सूचना की निर्भरता काफी बढ़ गई है। वर्तमान समय के संदर्भ में सूचना

आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह, शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है, जब आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो और जब जरूरत हो।

विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज पुस्तकालयों में शैक्षिक पुस्तकालयों का कार्य सूचना विस्फोट, सूचना अधिभार और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में क्रांतियों और क्रांतियों के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो गया है। आवेदन और शुद्ध विचार दोनों में नए विकास की भारी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दर्ज ज्ञान की बाढ़ आ गई है। हर साल पत्रिकाओं की एक मशरूम वृद्धि होती है, और लाखों शोध पत्र विशेष पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, जैसे कि लोकप्रिय पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने ज्ञान को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के लिए बुनियादी माध्यम को बढ़ाया है। संचार माध्यम ध्वनि चैनल और नेटवर्क सूचना प्रणाली के निर्माण से नए विस्तार और क्षितिज खुल रहे हैं।

आज, इसकी मात्रा, रूपों और स्वरूपों, इसके भंडारण और पुनर्प्राप्ति के तकनीकी पहलुओं और जिस तरह से इसका संचार किया गया है, के संदर्भ में जानकारी लगातार बदल रही है। इस स्थिति ने न केवल उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध जानकारी की मात्रा में वृद्धि की है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बनाया है जो उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ LIS पेशेवरों (लाइब्रेरियन) के लिए जानकारी (कौर) को खोजने, एक्सेस करने, मूल्यांकन करने और संभालने के मामले में जटिल है। (2009)। सूचना पेशेवरों और शिक्षकों के लिए यह स्थिति एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि दोनों समूहों में यह सुनिश्चित करने में रुचि होती है कि सूचना उपयोगकर्ताओं को उन विभिन्न समस्याओं को दूर करने में मदद की जाए जो उन्हें सूचना के चयन, पहुंच और उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं में मिलती हैं।

LIS पेशेवरों के लिए यह निर्धारित करने के लिए उच्च समय है कि किस सूचना की आवश्यकता है, कैसे चयन करें, इसे कहां प्राप्त करें, इसका मूल्यांकन करें और इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से उपयोग करें, सामूहिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण महत्व है। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग स्वयं को, दुनिया की समझ बनाने में सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नति ज्ञान, सूचना कौशल और शिक्षा और सफल जीवनयापन के लिए आवश्यक मूल्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है।

नतीजतन, सूचना साक्षरता शिक्षा के लिए केंद्रीय के रूप में एक उच्च प्रोफाइल प्राप्त कर रही है। यह गतिशील अवधारणा सीखने और समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से सूचना और तकनीकी रूप से समृद्ध वातावरण में आवेदन के लिए बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणना कौशल का विस्तार करती है (कुल्हथाऊ, 2001)। हालांकि, यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि यहां तक कि सबसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों में, सूचना आयु के लिए छात्रों को तैयार करने के प्रयास आंशिक रूप से सफल रहे हैं और सूचना कौशल अनुसंधान से सिफारिशों के कार्यान्वयन को धीमा और लागू करने में मुश्किल हुई है।

इन सभी पेचीदगियों ने ज्ञान के निर्माण और साझाकरण में इसके प्रभावी उपयोग के लिए इसकी प्रामाणिकता, वैधता और विश्वसनीयता का चयन करने और मूल्यांकन करने, कुशलता से जानकारी प्राप्त करने और प्राप्त करने में व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां सूचना साक्षरता (IL) की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की महत्वपूर्ण सोच और निरंतर सीखने के कौशल के लिए सूचना के उपभोग से पहले सूचना संसाधनों और स्वरूपों के भेदभाव को कम करने की क्षमता विकसित करना है।

बंडी (2004) कहते हैं, डिजिटल युग में, साक्षरता का अर्थ है कि सूचना प्रौद्योगिकी पर्याप्त नहीं है। सभी को क्या करना चाहिए, यह सीखना है कि उन अविश्वसनीय रूप से विविध और शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि सूचना को खोजने, पुनः प्राप्त करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और फिर विशिष्ट निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने के लिए इसका उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा सके। सूचना और प्रौद्योगिकी की सरासर प्रचुरता अपने आप में अधिक प्रभावी ढंग से जानकारी का उपयोग करने की क्षमता और क्षमता के पूरक समझ के बिना अधिक जानकारी प्राप्त शिक्षार्थियों का निर्माण नहीं करेगी। जब तक शिक्षार्थी सूचना साक्षर नहीं होते, तब तक उन्हें कुशलता से खोजने, व्यवस्थित करने और समीक्षकों द्वारा प्राप्त जानकारी का मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल में कमी होगी।

यूनेस्को की सभी कार्यक्रमों के लिए सूचना (आईएफएपी) लोगों तक पहुंचने और जानकारी का उपयोग करने के लिए कौशल से लैस करने की आवश्यकता पर जोर देती है: 'सूचना साक्षरता महत्वपूर्ण स्वागत, मूल्यांकन और सूचना के उपयोग के लिए कौशल और क्षमताओं के साथ व्यक्तियों

को लैस करके ज्ञान की खोज को बढ़ाती है। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में। यह मानता है कि हर किसी के पास सूचना साक्षरता कौशल को समझने, सक्रिय रूप से भाग लेने और उभरते ज्ञान समाजों (लॉन्गवर्थ, (एड।) (2005) से पूरी तरह से लाभ उठाने का अवसर होना चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान है, राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। शिक्षक की योग्यता, सूझबूझ कार्यक्षमता से ही भवन पाठ्यचर्या और उपकरणों का समुचित उपयोग कक्षाओं के अंदर हो सकता है। शिक्षक ही विद्यालय को प्राणवान बन सकता है। अध्यापक के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय का प्रतिफल सचमुच काफी मूल्यवान है क्योंकि उसके परिणामस्वरूप लाखों छात्रों की शिक्षा में जितना सुधारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन होगा शिक्षक की अभिक्षमता में भी उतनी ही वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्ताव ने भी इस तथ्य को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया है। “शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान को निर्धारित करने वाले घटकों में अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। उसका प्रभावशाली शिक्षण समाज में पारस्परिक स्नेह, मेलजोल तथा सद्भावना को बढ़ा सकता है तथा एक आदर्श समाजवादी समाज का निर्माण कर सकता है।” शिक्षण न केवल शैक्षणिक विधियों का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है बल्कि यह देश की युवा शक्ति भावनाओं को सही दिशा में मोड़ सकती है। हमारे देश की वर्तमान आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी तथा अत्यन्त कुशल व योग्य अध्यापकों की नितांत आवश्यकता है जो हमारे राष्ट्र व समाज की भावी आशाओं, आकांक्षाओं तथा सपनों को साकार रूप दे सके। जो छात्रों को आत्मनिर्भर, उपयोगी तथा नए समाज निर्माण में योगदान देने वाले भावी नागरिक तैयार करेगा।

एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए अध्यापक में जो गुण होने चाहिए वे गुण प्राप्त होते हैं। शिक्षकों की अच्छी शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा। अतः अच्छे व गुणवान शिक्षक समाज को प्रदान करते हैं शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय। जिस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास में एक अच्छे अध्यापक की भूमिका होती है। विद्यालय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है। शिक्षक बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। वह छात्रों को प्रगति की राह दिखाने वाला पथ-प्रदर्शक होता है। शिक्षक न केवल कक्षा में अपितु विद्यालय में उचित वातावरण का निर्माण करता है।

भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास

शुरुआत की औपचारिक तकनीकी शिक्षा में भारत कर सकते हो दिनांकित वापस मध्य 19 वीं सदी। प्रमुख नीतिगत पहलों में पूर्व स्वतंत्रता अवधि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति भी शामिल है में 1902, मुद्दे की भारतीय शिक्षा नीति संकल्प में 1904, और 1913 के गवर्नर जनरल की नीति बयान तकनीकी शिक्षा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना के महत्व पर बल बंगलौर में विज्ञान (IISc), कानपुर में चीनी, वस्त्र और चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान, 1905 में बंगाल में NCE और कई प्रांतों में औद्योगिक स्कूल। महत्वपूर्ण विकास में शामिल हैं - 1943 के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) की तकनीकी शिक्षा समिति का गठनय तैयारी की 1944 की सर्वेक्ट रिपोर्ट और गठन के तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) में भारत सरकार द्वारा 1945 मुक्त भारत के लिए किया था के लिए चेहरा उसके एक प्रमुख औद्योगिक एक में मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के महान चुनौती के साथ में थोड़े समय के। यह था करने के लिए एक संकीर्ण आधार पर इस कार्य को शुरू: 1947 में, देश केवल 930 स्नातकों का उत्पादन में इंजीनियरिंग और 320 स्नातकों में प्रौद्योगिकी। स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रौद्योगिकी में बहुत कम थीं और इंजीनियरिंग में लगभग कोई भी चीज नहीं थी।

तकनीकी शिक्षा का महत्व देश की आजादी के बाद और अधिक महसूस किया गया। में 1948 एनआर सरकार समिति नियुक्त किया गया था जो चार की स्थापना की सिफारिश की बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों, में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और देश के उत्तर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग लोकप्रिय राधाकृष्णन आयोग (1948- 49), के रूप में जाना में इस आयोग जो प्रस्तुत की गई थी की रिपोर्ट में 1949, मुख्य सिफारिशों किए गए थे, जिनमें से कुछ थे, आयोग भूमिका पर बल दिया की विश्वविद्यालयों में सीमाओं की उन्नति ज्ञान, अर्थात्, अनुसंधान, विशेष रूप से शुद्ध या मौलिक अनुसंधान, उद्योगों, प्रशासनिक या गैर-विश्वविद्यालय वैज्ञानिक संगठनों के लिए अधिक लागू क्षेत्रों को छोड़कर। तथ्य यह है कि वैज्ञानिक मानव शक्ति की जरूरतों को बहुत महान थे स्वीकार करते हुए, यह भी कुछ नए क्षेत्रों का सुझाव दिया की स्नातकोत्तर अध्ययन और समुद्री जीव विज्ञान, ललित कला, पुरातत्व, धारावाहिक विज्ञान और दुनिया के रूप में इस तरह के अनुसंधान मामलों।

राधाकृष्णन आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर विस्तृत ध्यान दिया और कवर किया, विस्तार से, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा और कुछ नए व्यावसायिक अध्ययन जैसे व्यवसाय प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन और औद्योगिक क्षेत्र रिश्ते। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी सिफारिश की ताकि वर्ष भर छात्रों के काम के लिए मूल्य संलग्न किया जा सके और उद्देश्य परीक्षण शुरू करने का सुझाव दिया जा सके। तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) एक तकनीकी जनशक्ति समिति का गठन किया था में आदेश संख्या पता लगाने के लिए की देश की जरूरत के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों। इसके अलावा, 1947 में दो और समितियों, द साइंटिफिक मैनपावर कमेटी और द ओवरसीज स्कॉलरशिप कमेटी की नियुक्ति की गई थी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) की स्थापना नवंबर 1945 में की गई थी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में। पब्लिक सांविधिक के साथ हुई। मानदंडों और मानकों की योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए प्राधिकरण, मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और पुरस्कार वगैरह की समानता बनाए रखना।

एआईसीटीई विधेयक 1987 के एआईसीटीई अधिनियम संख्या 52 के रूप में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था और 28 मार्च, 1988 से प्रभावी हो गया था। एआईसीटीई और इसके तहत काम करने वाले निकाय, इसकी भूमिका और कार्यों को निम्नलिखित उप विषय में संक्षेप में बताया गया था। एआईसीटीई की भूमिका और कार्य। भारतीय संविधान 26 पर अपनाया में वें जनवरी, 1949 व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण और श्रम' मदजतम का 25 था सूची तृतीय (सूची समवर्ती कार्य की की औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र और राज्य) में देश।

तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन की परिकल्पना राष्ट्रीय नीति पर शिक्षा (एनपीई) 1986 (पैरा 6.1) में सदी के अंत तक पुनः प्रत्याशित परिदृश्य के संदर्भ में की गई है। एक्शन ऑफ द प्रोग्राम (पीओए) 1992 ने तकनीकी शिक्षा, इंटरैक्शन नेटवर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के विभिन्न स्तरों के संबंध में सिस्टम, थ्रस्ट और दिशाओं के प्रबंधन को कवर करते हुए व्यापक रणनीतियों का सुझाव दिया है। इनमें से महत्वपूर्ण हैं: तकनीशियन शिक्षा का विकास, स्नातक पाठ्यक्रमों के विविधीकरण में स्नातकोत्तर शिक्षा पर विशेष

ध्यान, तकनीकी शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढीकरण और विस्तार, सतत और दूरस्थ शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रावधान, महिला शिक्षा, सहभागिता नेटवर्क वगैरह।

तकनीकी शिक्षा के लिए पहली विदेशी सहायता 1951 में यूनेस्को से मिली थी, इसके बाद यूएसए, यूएसएसआर, पश्चिम जर्मनी, कोलंबो योजना वगैरह। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISCA) बेंगलोर को मई, 1958 में एक विश्वविद्यालय में खड़ा किया गया था, जिसे 1911 में स्थापित किया गया था, जो टाटा परिवार के राजसी दान के लिए अपनी स्थापना का कारण है। आईआईएससी, बेंगलोर के अलावा, भारत सरकार ने 1951 में खरपुर में पाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 1958 में बॉम्बे, 1959 में मद्रास, 1960 में कानपुर और 1963 में दिल्ली में स्थापित किया था। और केंद्र सरकार द्वारा एक को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। 7 वीं योजना के दौरान असम में प्रौद्योगिकी संस्थान।

मई, 1971 में भारत सरकार ने योजना मंत्रालय के तहत एक नया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बनाया। पहले निकाय को तकनीकी शिक्षा के संगठन में भूमिका के कार्यकारी हाथ के रूप में कार्य करने के लिए इस्तीफा दे दिया गया था क्योंकि आज देश की प्रगति तकनीकी शिक्षा के विकास पर निर्भर करती है। केंद्र की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं।

1. समग्र रूप से देश के लिए विकास की एकीकृत योजना।
2. अखिल भारतीय महत्व के विशेष पाठ्यक्रम के लिए संस्थानों की स्थापना करना।
3. तकनीकी संस्थानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता करना।
4. उच्च मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी शिक्षा की प्रगति को देखना।

सबसे उत्साहजनक अग्रिम में उन्नीस अर्द्धशतक के दौरान भारतीय शिक्षा के क्षेत्र था गया में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र। 1951 में, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए केवल 53 कॉलेज और 89 डिप्लोमा संस्थान थे। लेकिन यह 144 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बढ़ गया था, 2899 छात्रों की कुल क्षमता वाले 2999 डिप्लोमा संस्थान देश में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री के लिए 65 संस्थानों के अलावा कार्यरत हैं। उम्मीद यह थी कि 1998 के अंत तक भारत के स्तर के साथ

तकनीकी आदमी बिजली की आवश्यकता को पूरा होगा की सुविधा पहले से ही बनाया। लेकिन अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका य एक मामले के रूप तथ्य की भारत सरकार उसे तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सबसे अच्छा स्तर देश के लिए पर्याप्त मानव शक्ति पैदा करता है कोशिश कर रहा था।

नई चुनौतियों का सामना करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास भारत सरकार के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) और भारतीय विज्ञान संस्थानों (IISc) की स्थापना देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए एक बड़ा कदम था।

इंजीनियरिंग कार्मिक समिति (ईपीसी) की सिफारिश पर 1955 में एक योजना आयोग का गठन किया गया था, केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त और सहकारी उपक्रमों के रूप में प्रारंभिक साठ के दशक में आठ क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आरईसी) की स्थापना की गई थी। 2 एनडी पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान चिंहित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी श्रमशक्ति प्रदान करना। इन संस्थानों को समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त निकायों के रूप में पंजीकृत किया गया था और अपने संबंधित क्षेत्रों में राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया गया था। सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त और सहकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। प्रत्येक आरईसी को एक अखिल भारतीय संस्थान के रूप में कार्य करना था जो छात्रों को भर्ती कर रहा था और देश के सभी हिस्सों से संकाय की भर्ती कर रहा था। इन कॉलेजों ने विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश की।

2003 में, सत्रह पूर्व क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के रूप में फिर से शुरू किया गया और केंद्र सरकार के वित्त पोषित संस्थानों के रूप में संभाला गया और विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 3 अन्य संस्थानों अर्थात् बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना, सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर और त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज, अगरतला ग्रहण कर लिया है, और परिवर्तित उन्हें प्रौद्योगिकी पर 28 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ में वें जनवरी 2004, 1 सेंट दिसंबर, 2005 और 1 सेंट अप्रैल, 2006 में क्रमशः। इस प्रकार एनआईटी की कुल संख्या 2006 तक 20 से ऊपर चला गया है इन संस्थानों रहे हैं उम्मीद करने के लिए हो सकता है पर बराबर के साथ

अन्य राष्ट्रीय स्तर तकनीकी संस्थानों और हो सक्षम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्नातक और शिक्षा के स्नातकोत्तर स्तर की मांग को पूरा करने में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी। एक अधिनियम, अर्थात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2007, तब से संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था ताकि सभी एनआईटी के लिए एक सामान्य वैधानिक ढांचा प्रदान किया जा सके। नई 10 एनआईटी मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए थे की इलेवन के दौरान मानव संसाधन विकास (एमएचआरडी), भारत सरकार की योजना।

भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 10 एनआईटी में से 6 स्थापित किए गए थे, वे एनआईटी सिक्किम, एनआईटी, अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी, मेघालय, एनआईटी, नागालैंड, एनआईटी, मणिपुर, एनआईटी, मिजोरम और अन्य 4 एनआईटी एनआईटी, गोवा थे। NIT, उत्तराखंड, NIT, दिल्ली और NIT, पुदुचेरी क्रमशः।

झारखंड में तकनीकी शिक्षा

उच्च शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को महसूस करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही झारखंड के लोगों के दिमाग में आया। तब तक, झारखंड अतीत के साथ लगभग निर्बाध निरंतरता के युग में रहता था। हालाँकि लोगों को स्कूली शिक्षा का कुछ ज्ञान था, उच्च शिक्षा का विचार लोगों के लिए अलग-थलग था और सुविधाएं लगभग पूर्ववर्ती राज्य में अनुपस्थित थीं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि झारखंड में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1946 में धनंजुरी (डीएम) कॉलेज की स्थापना के साथ हुई। एक समाज का विकास राज्य में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के प्रकार पर निर्भर करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति और औद्योगिक विकास तकनीकी शिक्षा के उत्पाद थे।

झारखंड राज्य के संदर्भ में, स्वतंत्रता से पहले तकनीकी शिक्षा पूरी तरह से उपेक्षित थी। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में, झारखंड है अभी भी बहुत पीछे में तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना की एक प्रभाव के रूप में में 1945 जो बाद में एक एआईसीटीई के रूप में पारित अधिनियम सं 52 में एआईसीटीई विधेयक पेश किया गया था जो 1987 में संसद के दोनों सदनों और प्रभाव के साथ अस्तित्व में आया 28 मार्च, 1988 से तकनीकी शिक्षा के लिए सांविधिक अखिल भारतीय परिषद के लिए एक दृश्य के साथ 12 मई 1988 को पुनः स्थापित किया गया था करने के लिए देश भर में उचित योजना और तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समन्वित विकास,

पदोन्नति के गुणात्मक विकास और विनियमन और उचित तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का रखरखाव। श्व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण और श्रम '26 जनवरी, 1949 को अपनाई गई भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सूची प्प् का 25 वें स्थान पर था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) द्वारा दी गई तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के सुझाव के साथ। माध्यमिक शिक्षा आयोग की 1952-1953 जो माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया दे, झारखंड सरकार के साथ भारत उद्यम सरकार ले लिया पहल को तकनीकी शिक्षा प्रदान में पहले तकनीकी संस्थान की स्थापना से राज्य में 22 दक, फरवरी 1956 में आदिम जाति शिक्षा आश्रम, चिंगमिरोंग, इम्फाल और आदिम जाति तकनीकी संस्थान के रूप में नामित। इसकी आधारशिला भारत के केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लव पंत ने रखी थी।।कपउरंजप तकनीकी संस्थान स्थापित किया गया था करने के लिए प्रस्ताव डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सिविल इंजीनियरिंग के लिए अनुसूची जनजाति देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की और अनुसूची जाति के छात्रों को। इस संस्थान को राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद, असम से संबद्धता मिली। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में धीरे-धीरे डिप्लोमा कोर्स भी 1960 से शुरू किया गया था। संस्था ने गैर-आदिवासी छात्रों को 60 (सिविल में 40, इलेक्ट्रिकल में 10 और मैकेनिकल में 10 की क्षमता के साथ प्रवेश देना शुरू किया। वर्तमान में संस्था की सेवन क्षमता 180 (सिविल में 60, इलेक्ट्रिकल में 40, मैकेनिक्स में 30, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में 30 और फार्मेसी में 20) है। अध्ययन के पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विकास गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए पर्यवेक्षी स्तर पर तकनीशियनों का उत्पादन करना है। यह 1987 से झारखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

श्रम और रोजगार, भारत सरकार के मंत्रालय के तहत, अर्ध प्रशिक्षित पाठ्यक्रमों की एक तकनीकी संस्थान स्थापित किया गया था। झारखंड के हर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किया गया था। ये संस्थान व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन आईटीआई को राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया और राष्ट्रीय काउंसिल फॉर ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेड (एनसीटीवीटी), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन किया गया। पर उपस्थित 11 आईटीआई का सेवन क्षमता के साथ 27 विभिन्न ट्रेडों प्रदान कर रहे हैं के 1640 छात्रों में झारखंड।

साहित्य की समीक्षा

नायर (2010) ने तीन व्यापक शीर्षों के तहत तकनीकी शिक्षा की समस्याओं पर एक अध्ययन किया: तकनीकी शिक्षा की तैयारी, स्वयं तकनीकी शिक्षा और सफल प्रशिक्षण। अध्ययन में पाया गया कि व्यावहारिक प्रशिक्षण उद्योग के साथ असंतोषजनक रूप से आयोजित किया गया था जिसमें बहुत कम रुचि थी। अध्ययन इस निष्कर्ष के साथ सामने आया है कि तकनीकी शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ समानांतर होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा, मानविकी और नवीन बुनियादी विज्ञान के शिक्षण के साथ-साथ बुनियादी कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है, जिस पर अधिक जटिल कौशल का अधिचरणा बाद के चरण में बनाया जा सकता है।

वर्मा (2013) ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति और संभावनाओं पर एक स्वतंत्र अध्ययन किया। उन्होंने पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सिफारिश की। इसमें प्री इंडक्शन, इन-सर्विस और रिफ्रेश कोर्स का संगठन शामिल है। यह रखरखाव, मरम्मत और निर्माण से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकता आधारित केंद्रों की स्थापना की भी सिफारिश की गई थी, और सेवा अन्य सिफारिशों में से एक थी।

ओसाम (2013) ने नदियों के राज्य में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच की। अध्ययन में पाया गया कि व्यावसायिक और तकनीकी स्कूलों में शिक्षण स्टाफ की गुणवत्ता मध्यम रूप से उच्च थी, लेकिन अपेक्षाकृत अपर्याप्त थी। नदियों के राज्य में व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल सुविधाएं भी अपर्याप्त और खराब स्थिति में थीं। चिंता के मुख्य मुद्दों में योग्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षकों की कमी शामिल है, विशेष रूप से अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, अपर्याप्त कार्यात्मक उपकरण और सुविधाएं, खराब वित्तपोषण रणनीतियों और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए चुनौतियां।

मैथेनी (2013) ने विस्कॉन्सिन टेक्निकल कॉलेज सिस्टम में मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन एजुकेशन (METTE) कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए उप-स्नातक शिक्षा के श्रम बाजार परिणामों की जांच की। यह पाया गया कि, लागू विज्ञान (एएएस) डिग्री धारकों के METTE सहयोगी ने अर्जित किया

और उच्चतम दर पर कार्यरत थे। हालांकि, METTEAAS के सापेक्ष लंबी अवधि और तकनीकी साख अर्जित करने का नकारात्मक प्रभाव, किसी भी क्रेडेंशियल को पूरा नहीं करने या गैर-METTE क्रेडेंशियल अर्जित नहीं करने की तुलना में 40 से छोटा था। METTE प्रोग्राम में प्रवेश करने वाली महिलाएं और अल्पसंख्यक छात्र रोजगार दर और वार्षिक आय दोनों में नुकसान में थे, जबकि पुराने छात्रों के लिए निष्कर्ष मिश्रित थे। जिन छात्रों ने शैक्षणिक रूप से हासिल किया, वे रोजगार की आय और दरों दोनों में महत्वपूर्ण लाभ में थे।

ब्रांड (2014) ने संयुक्त राज्य में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में सुधार की राजनीतिक चुनौती पर एक केस अध्ययन किया। अध्ययन में बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, अच्छी विश्लेषणात्मक और ठोस बुनियादी कौशल, नई नौकरियों, प्रौद्योगिकी और पुनर्गठित कार्य स्थल के साथ-साथ लचीले श्रमिकों, मजबूत ज्मतम भाषा, गणित, तर्क, समस्या को सुलझाने और विश्लेषणात्मक कौशल के साथ बहु कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कौशल।

कुलश्रेष्ठ और नायक (2015) ने पाया कि पिछले छह दशकों के दौरान भारत में उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों (HTEIS) की संख्या में 1 ए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने मौजूदा शैक्षिक आदानों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए भारतीय HTEIs की उच्च तकनीकी शिक्षा के विषय में जानकारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

अध्ययन का उद्देश्य

1. छात्रों के तकनीकी शिक्षा हित का उनके लिंग के संदर्भ में अध्ययन करना।
2. अपने क्षेत्र के संदर्भ में छात्रों के तकनीकी शिक्षा हित का अध्ययन करना

उपसंहार

झारखंड में तकनीकी शिक्षा समय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी हिस्सेदारी का योगदान देती है और हमारे राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रौद्योगिकी का प्रसार जारी रहेगा, लेकिन जब तक हितधारक आवश्यकता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक शैक्षिक प्रणाली अपने परिचय का विरोध करती रहेगी। उस समय, शिक्षक तकनीक सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे क्योंकि यह उन पर जोर देने के बजाय आवश्यक है। आईसीटी के उपयोग ने उन्नत खोजी सोच कौशल का प्रदर्शन किया है, जैसे रचनात्मकता,

समस्या समाधान, उच्च-क्रम सोच कौशल और ध्वनि तर्क, साथ ही बेहतर प्रभावी खोज खोज और पुनर्प्राप्ति कौशल के साथ। सूचना का तेजी से विकास, विज्ञान और इंजीनियरिंग की क्षमता सूचना साक्षर होने के लिए स्नातक गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा के हिस्से के रूप में सूचना कौशल और महत्वपूर्ण सोच कौशल हासिल करने की आवश्यकता है ताकि वे कार्यबल में उत्पादक भागीदार बन सकें और जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहें।

संदर्भ

1. सिद्ध केएस (1984); शिक्षा में अनुसंधान की पद्धति, (नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड), पी। 69
2. वाल्टर, आर। बॉर्ग और एमडी गैल (1983); शैक्षिक अनुसंधान एक परिचय, (न्यूयॉर्क: लॉन्गमैन ग्रीन एंड कंपनी), पी। 142
3. रिमर्स एचएच और एनएलगेज (1995); शैक्षिक मूल्यांकन और मापन, (न्यूयॉर्क: हार्पर एंड ब्रदर), पी। 85
4. अमीन सुरेखा पी (1995); उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुजरात के छात्रों के लिए व्यावसायिक हित सूची का निर्माण और मानकीकरण; (अहमदाबाद: गुजरात विश्वविद्यालय, पीएचडी अप्रकाशित शोध प्रबंध)।
5. पटेल लक्ष्मणभाई के। (1994); विजयनगर तालुका (अहमदाबाद: गुजरात विद्यापीठ, एम.फिल। अप्रकाशित शोध प्रबंध) के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की रुचि के अध्ययन का अध्ययन।
6. शाह राजुलय आर। (1999); अहमदाबाद जिले के कक्षा - 9 से 12 के छात्रों पर व्यावसायिक सूची का प्रयास। (अहमदाबाद: गुजरात विश्वविद्यालय, एमएड अप्रकाशित शोध प्रबंध)।
7. प्रजापति भानु बी (2000); कुछ चर (अहमदाबाद: गुजरात विश्वविद्यालय, एमएड अप्रकाशित शोध प्रबंध) के संदर्भ में अहमदाबाद शहर के शिक्षण पेशे के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

8. पटेल बालाभाई एम। (2002); कुछ चर के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के व्यावसायिक हित का अध्ययन। (अहमदाबाद: गुजरात विश्वविद्यालय, एमएड। अप्रकाशित शोध प्रबंध)।
9. त्रिवेदी अंकिता पी। (2006); माध्यमिक विद्यालयों (गुजरात विश्वविद्यालय, एमएड अप्रकाशित शोध प्रबंध) के शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि का एक अध्ययन।
10. पटेल कोकिलाबेन एम (2007); कादी तालुका (पाटन: हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, एमएड अप्रकाशित शोध प्रबंध) के माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के व्यावसायिक हित का अध्ययन।

Corresponding Author

Poonam Bala*

Research Scholar, Kalinga University, Raipur